प्रशासक प्रफुल पटेल की अध्यक्षता में हुई निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में हुए ऐतिहासिक फैसले

■ 130 उद्योगों को दी गयी सैद्धांतिक मंजूरी, प्रदेश में 560 करोड़ रुपये का होगा निवेश

■ संघ प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, अब तक की सबसे ज्यादा सब्सिडी राशि को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, सबसे अधिक संख्या में उद्योगों को हुआ लाभ

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 20 अगस्त। संघ प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन योजना 3-7-2015 में शुरू की गयी थी, ताकि प्रदेश को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके। वस्त्र क्षेत्र एवं कौशल विकास क्षेत्र उद्योगों को मजबूत किया जा सके, उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके एवं निवेश लाकर स्थानीय आबादी को रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जा सके। इस योजना में कुल 10 घटक हैं, जैसे कि नए एवं पुराने विस्ताराधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए पूंजी सब्सिडी एवं ब्याज सब्सिडी, गुणवत्ता प्रमाण पत्र के लिए सहायता, पेटेंट पंजीकरण के लिए सहायता, ऊर्जा एवं पानी की बचत के लिए सहायता, स्थानीय रोजगार के लिए प्रोत्साहन, कौशल विकास के लिए सहायता, तकनीकी कपड़ा क्षेत्र एवं कपड़ा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अधिग्रहण के ब्याज सब्सिडी आदि। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन योजना के आकर्षण के कारण बड़े निवेश को आकर्षित किया है। वर्ष 2016 से 2020 तक कुल 3905 नए उद्योगों की स्थापना की गई जिसमें 3874 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं 31 बड़े उद्योगों शामिल है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में 1859 सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज एवं 2046 विनिर्माण इकाइयों ने निवेश किया है, जिससे 64111 नए रोजगार उत्पन्न हुए है एवं 2867 करोड़ का निवेश हुआ है। इस में बड़े उद्योगों ने 1421 करोड़ का निवेश किया एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ने 1446 करोड़ का योगदान दिया। इस योजना की शुरूआत के बाद से प्रशासन ने दादरा और नगर हवेली के लिए निवेश संवर्धन परिषद की 10 और दमण और दीव के लिए 8 बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। वर्ष 2016 से 2020 तक प्रदेश में कुल 53 इकाइयों को 19.2 करोड़ की सब्सिडी दी गयी है। इसमें कपड़ा इकाइयों को 10.71 करोड़ और प्लास्टिक इकाइयों को 6.37 करोड़ की सब्सिडी दी गई। दादरा और नगर हवेली की 11वीं और दमण की 9वीं निवेश संवर्धन परिषद बैठक 19 अगस्त 2020 को प्रशासक प्रफुल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें 130 उद्योगों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी जिससे प्रदेश में 560 करोड़ रुपये के निवेश है। निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर परिषद में चर्चा की गई और आवेदनों की जांच के बाद प्रदेश के 35 उद्योगों को 14.38 करोड़ रुपये की सब्सिडी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी। निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा सब्सिडी राशि को दी गई सैद्धांतिक मंजूरी योजना की शुरूआत से अब तक की सबसे अधिक राशि है। प्रशासन का यह कदम उद्योगों के विकास के लिए एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने एवं स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसरों का बढ़ाने का संघ प्रदेश प्रशासन का सक्रिय दृष्टिकोण को दशार्ता है। सब्सिडी सहायता का दावा करने से लेकर सब्सिडी सहायता के समय पर वितरण करने हेतु एवं इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए प्रशासक प्रफुल पटेल ने निर्देश दिये। प्रशासक ने यह भी कहा कि संघ प्रशासन की योजनाओं के बारे में हितधारकों में अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि सभी पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठा सकें एवं प्रदेश के लोगों का कल्याण हो सके। इसीके साथ निवेश प्रोत्साहन परिषद ने यह बताया कि समय-समय पर परिषद की बैठके करना जरूरी है जिससे उद्योगों को मौजूदा लाभों का फायदा उठाने में अधिक सहायता मिलेगी। आज की निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक को संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमण एवं दीव के उद्योग के अनुकूल दृष्टिकोण के रूप में सदैव याद किया जाएगा। प्रशासन के इस अभूतपूर्व निर्णय से औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश होगा, जिससे संघ प्रदेश के लोगों का कल्याण होगा।